भारत - अफगानिस्तान संबंध

राजनीतिक

भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंध बहुत मजबूत हैं जो ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संपर्कों पर आधारित हैं। यह संबंध नई दिल्ली एवं काबुल में सरकारों तक सीमित नहीं है तथा इसकी नींव लोगों के बीच ऐतिहासिक संपर्कों एवं आदान - प्रदान टिकी है। हाल के दिनों में, भारत - अफगान संबंध वर्ष 2011 में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सामरिक साझेदारी करार से और सुदृढ़ हुए हैं। या। जैसा कि अफगानिस्तान 2015 में राजनीतिक, सुरक्षा एवं आर्थिक संक्रमण के लिए एक साथ स्वयं को तैयार कर रहा था, भारत ने अफगानिस्तान की सुरक्षा एवं विकास के लिए एक दीर्घावधिक प्रतिबद्धता करके अपने भविष्य के बारे में उसके भय को दूर किया था।

दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी करार (एस पी ए) में अन्य बातों के साथ अफगानिस्तान की अवसंरचना एवं संस्थाओं, शिक्षा के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए सहायता तथा विभिन्न क्षेत्रों में अफगानिस्तान की अपनी क्षमता फिर से निर्मित करने में सहायता प्रदान करना, अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों में निवेश को प्रोत्साहित करने, अफगान के नेतृत्व में, अफगानिस्तान के स्वामित्व में शांति एवं सामंजस्य की विस्तृत एवं समावेशी प्रक्रिया के लिए अफगानिस्तान के निर्यात के समर्थन के लिए भारतीय बाजार में ड्यूटी फ्री अक्सेस प्रदान करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा अफगानिस्तान को स्थाई एवं दीर्घावधिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता की वकालत करने का प्रावधान है। हार्ट ऑफ एशिया की व्यापार, वाणिज्य एवं निवेश सी बी एम प्रक्रिया के लीड देश के रूप में भारत ने जनवरी, 2014 में नई दिल्ली में हार्ट ऑफ एशिया के देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया तथा फिक्की की मदद से भारत नवंबर 2015 में नई दिल्ली में छठवीं क्षेत्रीय तकनीकी समूह (आर टी जी) का आयोजन कर रहा है।

विदेश राज्य मंत्री जनरल वी के सिंह के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल ने अक्टूबर, 2014 में बीजिंग में हार्ट ऑफ एशिया मंत्री स्तरीय बैठक में और दिसंबर, 2015 में लंदन सम्मेलन में भाग एम एण्ड ई आर प्रभाग के सचिव श्री सुजाता मेहता के नेतृत्व में एक भारतीय शिष्टमंडल ने सितंबर 2015 में काबुल में आयोजित आर ई सी सी ए 6 सम्मेलन में भाग लिया।

अफगानिस्तान के साथ उच्च स्तर पर राजनीतिक भागीदारी भी होती है जो उच्च स्तर पर अनेक द्विपक्षीय यात्राओं से प्रतिबिंबित होती है। है। दोनों पक्षों की ओर से उच्च स्तर पर अक्सर यात्राएं होती रहती हैं जिसमें अन्यों के अलावा, मई, 2011 में प्रधानमंत्री की यात्रा; मार्च, 2014 (एफ वी पी मार्शल फहीम के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए) लिए उप राष्ट्रपति की यात्रा; एवं सितंबर, 2014 में राष्ट्रीय एकता सरकार के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री की यात्रा; जनवरी, 2011 में विदेश मंत्री फरवरी, 2014 और सितंबर, 2014 में विदेश मंत्री की यात्रा; मार्च, 2011, फरवरी, 2013 और अक्टूबर, 2014

में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एन एस ए) की यात्रा; अंतर्राष्ट्रीय संपर्क समूह की बैठक के लिए जून, 2011 में प्रधानमंत्री के विशेष दूत की काबुल यात्रा; सितंबर, 2011, अगस्त, 2013 और मई, 2014 में विदेश सचिव की यात्रा; सितंबर, 2011 और जून, 2014 में विधि एव न्याय मंत्री की यात्रा, इस्पात मंत्री की अप्रैल में यात्रा तथा भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद में प्रधानमंत्री के सलाहकार श्री एस रामादोरई और राष्ट्रीय कृषक आयोग के अध्यक्ष श्री एम एस स्वामीनाथन की यात्रा शामिल की यात्रा शामिल हैं।

माननीया विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने अफगानिस्तान का दौरा किया तथा राष्ट्रपति करजई से मुलाकात की और 10 सितंबर, 2014 को एक स्मारक अफगान फ्लैग का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। यह फ्लैग, जो अफगानिस्तान की एकता एवं राष्ट्रवाद का प्रतीक है, का आयोजन विभिन्न प्रायोजकों की सहायता से किया गया जिसमें फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया शामिल है। भारत ने फ्लैग के चारों ओर राष्ट्रीय सार्वजनिक पार्क के निर्माण के लिए 1 मिलियन अमरीकी डालर की घोषणा की। भारतीय पहल की अफगानिस्तान के नागरिकों एवं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा बड़े पैमाने पर सराहना की गई। विदेश मंत्री महोदया ने काबुल में नए चांसरी परिसर का भी उद्घाटन किया जहां से दूतावास ने जुलाई, 2014 से काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि यह भारत द्वारा 'नो एक्जिट' पॉलिसी का सबसे स्पष्ट उल्लेख है। हार्ट आफ एशिया 2015 के दौरान माननीया विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने इस्लामाबाद का दौरा किया। सम्मेलन में विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान के साथ संपर्क, क्षेत्रीय व्यापार बढ़ाने तथा खुलेपन पर जोर दिया और इस संबंध में "पाकिस्तान के लिए भारत की ओर से सहयोग का हाथ बढ़ाया"।

अफगानिस्तान की ओर से, भारत की उच्च स्तरीय यात्राओं में निम्नलिखित शामिल हैं : पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने मई, 2013 में भारत की यात्रा की जो नवंबर, 2012 में उनकी राजकीय यात्रा के तुरंत बाद थी, जब उन्होंने प्रतिष्ठित मौलाना अब्दुल कलाम आजाद स्मारक व्याख्यान दिया था, राजनीतिक एवं कारोबारी नेताओं के साथ गहन बातचीत की थी तथा भारत के साथ चार एम ओ यू पर हस्ताक्षर के साक्षी बने थे। भारत ने अफगान संसद के उच्च सदन के लिए 11 से 18 फरवरी, 2013 के दौरान एक अध्ययन दौरे की भी मेजबानी की। पूर्व राष्ट्रपति श्री हामिद करजई ने मई, 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भारत का दौरा किया। एचटी लीडरशिप शिखर बैठक में भाग लेने के लिए श्री नवंबर, 2014 में भारत का दौरा किया तथा उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आयोजित पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती में भी भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर, 2014 कें काठमांडू में सार्क शिखर बैठक के दौरान अतिरिक्त समय में राष्ट्रपति डा. गनी से मुलाकात की। दिसंबर, 2014 में पास आउट परेड में मुख्य अतिथि के रूप में जनरल करीबी ने आई एम ए, देहरादून का दौरा किया तथा सी ओ ए एस जनरल सुहाग से भी मुलाकात की।

2014 में, अफगानिस्तान में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। दो चक्रों वाली चुनाव की लंबी चुनावी प्रक्रिया तथा संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में लेखा परीक्षा प्रक्रिया के बाद दो अग्रणी उम्मीदवारों - डा. अशरफ गनी और अब्दुल्लाह अब्दुल्लाह के बीच एक राजनीतिक करार पर हस्ताक्षर किया गया जिससे राष्ट्रीय एकता सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ जिसने 29 सितंबर, 2014 को शपथ ग्रहण किया। शपथ - ग्रहण समारोह में हमारे उप राष्ट्रपति डा. हामिद अंसारी ने भाग लिया। राजनीतिक समावेशन तथा सत्ता के शांतिपूर्ण अंतरण पर हमारे निरंतर संकेत पर ध्यान दिया गया तथा अफगानिस्तान के सभी वर्गों द्वारा इसकी सराहना की गई। अपने बधाई संदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूरे दिल से अफगानिस्तान के दो नेताओं के बीच करार का स्वागत किया तथा कहा कि उन्होंने जो बुद्धिमतता दर्शाई है वह अफगानिस्तान के लोगों की मजबूत लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का सम्मान करती है जो चुनावों में मतदान की संख्या से भी सपष्ट होता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत अफगानिस्तान की नई सरकार के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा, जैसे कि यह एक मजबूत, विकसित एवं शांतिपूर्ण राष्ट्र के निर्माण के कार्य में निरंतर लगा हुआ है।
14 मार्च 2015 को मुख्य कार्यपालक अब्दुल्ला अब्दुल्ला तीन दिवसीय यात्रा के लिए भारत पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने भारत के उप राष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी तथा कुछ अन्य उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने इंडिया टुडे पत्रिका द्वारा आयोजित भारत गोष्ठी सम्मेलन में भी भाग लिया। 7 माह बाद अप्रैल 2015 में राष्ट्रपति डा. अशरफ गनी ने अप्रैल 2015 में भारत का आधिकारिक दौरा किया। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति गनी ने भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, आपदा प्रबंधन, ऊर्जा क्षेत्र तथा निर्वाचन प्रबंधन सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग एवं सहायता के बारे में चर्चा की। राष्ट्रपति गनी की यात्रा के परिणामस्वरूप भारत ने अफगानिस्तान को तीन चीतल हेलीकाप्टर उपहार में दिया है; मैसर्स हबिबियार स्कूल, काबुल और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य संस्थान के वार्षिक अनुरक्षण के लिए सहायता; 5 वर्ष के लिए भारत में कोंजेनिटल हार्ट डिजीज (सी एच डी) से पीड़ित अफगानी बच्चों के उपचार के लिए ए आर सी एस को 5 मिलियन अमरीकी डालर का वित्त पोषण; 2020 तक आई सी सी आर छात्रवृत्ति का विस्तार तथा एक दूसरे के देशों में यात्रा करने के लिए दोनों पक्षों के वाहनों को अनुमति प्रदान करने के लिए द्विपक्षीय मोटर वाहन संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी तत्परता का संकेत दिया।

अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहम्मद हनीफ अटमार ने 8 और 9 नवंबर 2015 को भारत का दौरा किया। अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भारत सरकार के संगत प्राधिकारियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठकों के दौरान अफगानिस्तान में तथा इस क्षेत्र में वर्तमान स्थिति सहित राजनीतिक, सुरक्षा एवं आर्थिक सहयोग के क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तथा भारतीय प्राधिकारियों ने सामरिक साझेदारी करार के प्रावधानों के अनुसरण में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में परस्पर प्रयासों पर चर्चा की तथा विचारों का

आदान प्रदान किया। जहां तक द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग का संबंध है, महामहिम अटमार ने भारतीय प्राधिकारियों के साथ अफगानिस्तान में भारतीय कंपनियों द्वारा निवेश की गति बढ़ाने पर चर्चा की।

अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्य के उप विदेश मंत्री हेकमत खलील करजई ने 16 से 20 नवंबर 2015 के दौरान नई दिल्ली का आधिकारिक दौरा किया। अपनी चार दिवसीय यात्रा के दौरान उप विदेश मंत्री करजई ने अनेक मुद्दों पर चर्चा करने तथा भारत और अफगानिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति पर चर्चा करने के लिए भारतीय प्राधिकारियों के साथ बैठकें की और भारत आधारित थिंकटैंक के साथ बातचीत की। अनेक संगत प्रतिनिधियों के साथ अफगानिस्तान के उप विदेश मंत्री ने भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा की। अफगानिस्तान के प्राधिकारी ने भारत के माननीय उप राष्ट्रपति महामहिम हामिद अंसारी, विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री श्री राजीव प्रताप रूड़ी, विदेश सचिव डा. एस जयशंकर, विशेष सचिव (ई आर) श्रीमती सुजाता मेहता, गृह सचिव श्री राजीव महर्षि, बी सी सी आई महासचिव श्री अनुराग ठाकुर तथा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के महानिदेशक श्री सी वी राजशेखर से मुलाकात की। उप विदेश मंत्री ने मेजबान देश के प्राधिकारियों के साथ भारत और अफगानिस्तान के बीच द्विपक्षीय करारों के अलावा दोनों देशों के लिए आपसी हित एवं सरोकार से जुड़े अनेक प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। अफगानी शिष्टमंडल के प्रमुख ने चौथम हाउस रूल के तहत विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन (वी आई एफ) के सदस्यों से भी बातचीत की तथा "भारत - अफगानिस्तान संबंध : आगे की राह" पर प्रेक्षक अनुसंधान प्रतिष्ठान में भाषण दिया। इस यात्रा के दौरान अफगानिस्तान के प्राधिकारी ने नेशनल कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी तथा बी जे पी के राष्ट्रीय महासचिव श्री राम माधव से भी मुलाकात की।

25 दिसंबर 2015 को एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति अशरफ गनी से मुलाकात की; उन्होंने मुख्य कार्यपालक डा. अब्दुल्ला तथा पूर्व राष्ट्रपति श्री हामिद करजई के साथ बैठक की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने नव निर्मित अफगान संसद का उद्घाटन किया; उन्होंने अफगानिस्तान एवं भारत दोनों देशों के स्कूलों एवं कालेजों में अफगान सुरक्षा बलों के शहीदों के बच्चों के लिए 500 छात्रवृत्तियों की घोषणा की तथा प्रधानमंत्री ने अफगान एयरफोर्स को चार एमआई25 अटैक हेलीकाप्टर उपहार में दिया। इस यात्रा के दौरान 4 संयुक्त कार्य समूहों की बैठकों के साथ 2016 की पहली तिमाही में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की अध्यक्षता में सामरिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक का आयोजन करने का निर्णय लिया गया।
अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्य के मुख्य कार्यपालक महामहिम डा. अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने 31 जनवरी से 4 फरवरी 2016 के दौरान भारत का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने 1 फरवरी से प्रधानमंत्री से मुलाकात की तथा अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति तथा शांति एवं सामंजस्य सहित आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने क्रमश: 1 और 4 फरवरी को महामहिम डा. अब्दुल्लाह

से मुलाकात की। भारत ने अफगानिस्तान के निरंतर राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक संक्रमण के दौरान सभी संभव तरीकों से अफगानिस्तान का साथ देने की अपनी अटल प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान में और भारत में पठानकोट में हाल के आतंकी हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की और सभी रूपों एवं अभिव्यक्तियों के आतंकवाद एवं इसके समर्थन का पूरी तरह सफाया करने तथा इस क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता की आवश्यकता पर जोर दिया।

निरंतर द्विपक्षीय विकास सहयोग के संदर्भ में अफगानिस्तान में 92 परियोजनाओं से युक्त लघु विकास परियोजनाओं के तीसरे चरण के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदन के निर्णय के बारे में बताया गया। दोनों पक्ष प्राथमिकता के आधार पर ईरान में चाहबहार बंदरगाह के माध्यम से संपर्क विकसित करने पर सहमत हुए। राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा की आवश्यकता से छूट के लिए करार पर हस्ताक्षर किया गया। 3 फरवरी को महामहिम डा. अब्दुल्लाह ने भारत में 3 प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग चैंबरों अर्थात एसोचैम, सी आई आई और फिक्की के साथ संयुक्त वार्ता को संबोधित किया।

महामहिम डा. अब्दुल्लाह ने 2 फरवरी को जयपुर में इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित आतंकवाद की खिलाफत पर सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया, जहां उद्घाटन भाषण राष्ट्रपति जी द्वारा दिया गया।

वाणिज्यिक संबंध

भारत - अफगान, व्यापार एवं निवेश

भारत 3000 वर्षों से मध्य, दक्षिण एवं पश्चिम एशिया के बीच व्यापार मार्गों के जंक्शन के रूप में अफगानिस्तान के महत्व को स्वीकार करता है। 2013-14 के लिए 683.02 मिलियन अमरीकी डालर का द्विपक्षीय व्यापार (भारत द्वारा 474.25 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का निर्यात और 208.77 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का आयात) और 2014-15 के लिए 684 मिलियन अमरीकी डालर (भारत द्वारा 422 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का निर्यात और 262 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का आयात) वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। तथापि व्यापार संबंध अपनी सही क्षमता को साकार कर सकते हैं यदि अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय व्यापार के लिए वाघा - अटारी मार्ग को खोल दिया जाए। अब तक इस संबंध में अफगानिस्तान - पाकिस्तान पारगमन व्यापार करार (ए पी टी टी ए) प्रतिबंधात्मक रहा है। पाकिस्तान के बाद भारत अफगानिस्तान का प्रमुख निर्यात गंतव्य है। भारत द्वारा जोरांग - डेलाराम सड़क के निर्माण के उद्देश्यों में से एक अफगानिस्तान के समुद्री बंदरगाह को एक और आउटलेट प्रदान करने के अलावा द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तेजी लाना है। ईरान में चाबहार बंदरगाह के सफल प्रचालन से इस सड़क का उपयोग हो सकता है जिससे भारत में अफगानी उत्पादों के लिए एक नया पारगमन मार्ग उपलब्ध होगा और साथ ही

भारत के लिए तथा पूरी दुनिया के लिए मध्य एशिया के साथ व्यापार करने के लिए एक नया मार्ग प्राप्त होगा।

भारत और अफगानिस्तान ने मार्च 2003 में एक तरजीही व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत भारत ने अफगानिस्तान के सूखे मेवों की कितपय श्रेणी को 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत (38 गुना) तक की पर्याप्त ड्यूटी रियायत प्रदान की है। बदले में अफगानिस्तान ने चाय, चीनी, सीमेंट और फार्मास्युटिकल सहित भारतीय उत्पादों को इसी तरह की रियायत प्रदान की है। नवंबर, 2011 में, भारत ने माले में आयोजित सार्क शिखर सम्मेलन में सार्क के सभी सबसे कम विकसित देशों के लिए बुनियादी सीमा शुल्क को हटा लिया जो अफगानिस्तान के सभी उत्पादों (अल्कोहल एवं तंबाकू को छोड़कर) को भारत के बाजार में ड्यूटी फ्री अक्सेस प्रदान किया। सबसे कम विकसित देश के रूप में अफगानिस्तान ने साफ्टा पर हस्ताक्षर किया है तथा सभी माल, जो संवेदनशील सूची में शामिल नहीं हैं, पर अपनी टैरिफ दर में 5 प्रतिशत या इससे कम कमी लाने की अपेक्षा है। इस एक दशकीय प्रक्रिया से टैरिफ में किसी अचानक या नाटकीय कटौती से बचने और अफगान उद्योग के लिए मामूली व्यवधान के साथ परिवर्तनों को सरलता से लागू करने में मदद मिली है। हाल ही में अफगानिस्तान ने मोटे तौर पर अपनी कुल 6000 टैरिफ लाइनों में से 1063 टैरिफ लाइनों की अपनी संवेदनशील सूची को घटाकर 850 किया है। अफगानिस्तान की संवेदनशील सूची में शामिल मात्र 30 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर टैरिफ की दर अपेक्षित से 5 प्रतिशत अधिक है। अफगानिस्तान की संवेदनशील सूची के तहत सर्वाधिक टैरिफ दरें फलों, सब्जियों एवं गिरियों, निर्माण की बुनियादी सामग्रियों, पेय पदार्थों, प्लांट, चमड़े की वस्तुओं एवं गलीचों पर लागू हैं। कुछ अन्य वस्तुएं, जिनका उत्पादन अफगानिस्तान में नहीं होता है, भी राजस्व संग्रहण के प्रयोजनों के लिए उच्च टैरिफ दरों के अधीन हैं, जैसे कि तंबाकू, सिरेमिक उत्पाद, पर्फ्यूम, खनिज एवं ईंधन।

वाघा बार्डर से भारतीय माल के निर्यात की अनुमति न होने तथा कराची बंदरगाह पर विलंब के कारण भारत - अफगानिस्तान व्यापार में पारगमन एक बड़ी समस्या है। ईरान में बंडार अब्बास बंदरगाह के जरिए या दुबई के माध्यम से अधिकांश व्यापार होता है। अमरीकी प्रतिबंधों के कारण बैंक / बीमा कंपनियां पहले बंडार अब्बास बंदरगाह के जरिए अपनी सेवाएं प्रदान करने से इन्कार कर रही थीं परंतु प्रतिबंधों के हट जाने के कारण अब स्थिति बदल सकती है। अनेक भारतीय कंपनियां अफगानिस्तान के अवसंरचना विकास से जुड़ी हुई हैं तथा देश के विकास में योगदान दे रही हैं।

हाल की अवधि में दोनों देशों के कारोबारी शिष्टमंडलों द्वारा एक दूसरे के देशों की काफी यात्राएं की गई हैं। हाल के समय में महत्वपूर्ण भारत / अफगानिस्तान व्यापार / व्यवसाय शिष्टमंडलों में निम्नलिखित शामिल हैं जिन्होंने भारत / अफगानिस्तान का दौरा किया है :

1 से 15 फरवरी 2015 तक सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला : इस कार्यक्रम का आयोजन हरियाणा राज्य पर्यटन विभाग द्वारा किया गया तथा इसमें अफगानिस्तान के 7 शिल्पियों ने भाग लिया। उनको मुफ्त में बूथ प्रदान किए गए। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है।

7वां एम पी एक्सपोटेक 2015 : रिवर्स क्रेता - विक्रेता बैठक 16 - 18 जनवरी 2015; ग्वालियर, मध्य प्रदेश। इस कार्यक्रम में 28 अफगानी प्रतिभागियों ने भाग लिया।

अहमदाबाद में फार्मेक्सिल अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी : 9 और 10 जनवरी 2015 को इस कार्यक्रम में 45 अफगानियों ने भाग लिया।

वाइब्रेंट गुजरात 2015 : अहमदाबाद में 11 जनवरी 2015 को इस कार्यक्रम में अफगानिस्तान के 45 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इंडिया स्टोन मार्ट 29 जनवरी - 1 फरवरी 2015 : 18 अफगानी प्रतिभागियों ने भाग लिया। फिक्की तथा यू एस ए आई डी (ए टी ए आर) की सहायता से टी सी आई सी बी एम प्रक्रिया के तहत अफगानिस्तान की भागीदारी के लिए सहायता प्रदान की गई।

नवीकरणीय ऊर्जा शिखर बैठक, दिल्ली, अगस्त 2015 : एच ओ एम के नेतृत्व में 43 सदस्यों के शिष्टमंडल ने इस शिखर बैठक में भाग लिया।

भारतीय फार्मास्यूलिकल्स एंड हेल्थ केयर एक्सपो, काबुल, 28 से 31 मई, 2015 : 12 भारतीय फार्मास्युटिकल कंपनियों ने भाग लिया।

नई दिल्ली में 14 से 17 नवंबर 2015 के दौरान 35वां आई आई टी एफ 2015 : 24 अफगानी कंपनियों ने 14 से 27 नवंबर 2015 के दौरान प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 35वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आई आई टी एफ, 2015) में भाग लिया तथा अपने उत्पादों जैसे कि केसर, सूखे मेवों, कारपेट, ज्वेलरी तथा हस्तशिल्प का प्रदर्शन किया।

पंजाब इंटरनेशनल एक्सपो, अमृतसर 2015, 4 से 6 दिसंबर 2015 : के सी सी आई से 20 सदस्यों ने इस एक्सपो में भाग लिया।

राइस एक्सपो, काबुल, 8 से 11 दिसंबर 2015 जो अफगान एक्सपो सेंटर, काबुल द्वारा आयोजित किया गया।

9वां एम पी एक्सपो, 29 से 31 जनवरी 2016 : के सी सी आई से 22 सदस्यों ने भाग लिया।

30वां सूरजकुंड मेला, 1 से 15 फरवरी 2016 : मिशन द्वारा अफगानिस्तान के छः प्रतिभागियों को नामित किया गया है। विदेश मंत्रालय के सार्क प्रभाग द्वारा इस कार्यक्रम की सहायता की जा रही है।

भारत - अफानिस्तान सांस्कृतिक संबंध

अफगानिस्तान पिछले 2000 वर्षों से अधिक समय से एक महत्वपूर्ण व्यापार एवं शिल्प केन्द्र रहा है जो भारत के साथ पर्सिया, मध्य एशिया की सभ्यताओं को जोड़ता है। तथापि पिछले तीन दशकों से चल रहे युद्ध के कारण कला एवं वास्तुशिल्प की अफगानिस्तान की अनोखी परंपराएं नष्ट हो गई हैं। आज अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने प्राचीन कला एवं वास्तुशिल्पीय विरासत की फिर से खोज करना और बनाए रखना, अफीम के गैर कानूनी व्यापार पर रोक लगाना और सबसे कमजोर समुदायों, विशेष रूप से महिलाओं एवं ग्रामीण आबादी को रोजगार प्रदान करना है। भारत और अफगानिस्तान सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं जो संगीत, कला, वास्तुशिल्प, भाषा और व्यंजन के क्षेत्रों में गहरे संबंधों पर आधारित है।

* विशेष रूप से संगीत के क्षेत्र में प्राचीनकाल में अफगानिस्तान के अधिकांश संगीतज्ञ पटियाला घराने में प्रशिक्षित थे।
* आज भारतीय फिल्में, गीत तथा टी वी सीरियल अफगानिस्तान की जनता में बहुत लोकप्रिय हैं तथा भारतीय सामाजिक - सांस्कृतिक मूल्य प्रणाली के साथ हिंदी को लोकप्रिय बनाने में काफी योगदान कर रहे हैं।
* सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की, कुम कुम एवं कहानी घर घर की, सारे गा मा पा, प्रतिज्ञा, उतरन जैसे टी वी सीरियलों को डारी भाषा में डब किया गया है। इनको देखने वाले दर्शकों की समग्र संख्या सर्वाधिक है तथा राष्ट्रीय एवं निजी टी वी चैनलों पर इनको प्राइम टाइम स्लाट के रूप में दिखाया जाता है। अफगानिस्तान के लिए भारत के पुनर्निर्माण कार्यक्रम के अंग के रूप में भारत ने ऐसी परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा है जिससे अफगानिस्तान की सांस्कृतिक विरासत संपोषणीय होगी। भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र साझी सांस्कृतिक विरासत को सुदृढ़ करने की दिशा में काम कर रहा है।

अफगानिस्तान में भारतीय समुदाय

मिशन अफगानिस्तान में रहने वाले भारतीयों का एक डाटाबेस रखता है, हालांकि अनेक भारतीयों ने मिशन के साथ अपना पंजीकरण नहीं कराया है। इस समय, एक अनुमान के अनुसार अफगानिस्तान में भारतीयों की संख्या 3500 के आसपास है, हालांकि उनमें से केवल लगभग 850 मिशन के यहां पंजीकृत हैं। अधिकांश भारतीय समुदाय बैंकों, आई टी फर्मों,

निर्माण कंपनियों, अस्पतालों, गैर सरकारी संगठनों, दूर संचार कंपनियों, सुरक्षा कंपनियों, विश्वविद्यालयों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं, अफगानिस्तान सरकार तथा यू एन मिशनों में पेशेवर के रूप में काम कर रहा है। मिशन भारतीय नागरिकों के साथ निकटता से संपर्क बनाए रखता है और उनकी समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है तथा राष्ट्रीय समारोहों तथा दूतावास के समारोहों में शामिल होने के लिए उनको नेमी तौर पर आमंत्रित करता है। अफगानिस्तान में कारोबार करने वाली प्रमुख भारतीय कंपनियों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) बी एस सी एवं सी एण्ड सी - नई संसद परियोजना
(2) के ई सी - विद्युत पारेषण लाइन
(3) फोनिक्स - विद्युत पारेषण में परामर्श
(4) ए आई पी एल - हिलमंड प्रांत में जल विद्युत परियोजना की स्थापना
(5) वापकोस - सलमा बांध
(6) एंजलिक इंटरनेशनल - सलमा बांध तथा अन्य विद्युत परियोजनाएं
(7) एप्टेक - कंप्यूटर एवं प्रबंध शिक्षा
(8) गैमन इंडिया - विद्युत पारेषण लाइन तथा विद्युत उप केन्द्र
(9) के पी टी एल - विद्युत पारेषण लाइन
(10) अनार ग्रुप (एयर इंडिया जी एस ए)
(11) स्पाइस जेट

मिशन ने 2014 में 99 विपदाग्रस्त भारतीयों की भारत वापसी की व्यवस्था की, जबकि 2015 में (आज तक) 58 भारतीयों की भारत वापसी की व्यवस्था की है, जो वीजा समाप्त हो जाने अथवा पासपोर्ट खो जाने के कारण अथवा धन के अभाव में अफगानिस्तान में फंसे हुए थे। अधिकांश मामलों में एजेंटों को मनमाने रकम के भुगतान के बाद अफगानिस्तान में आकर्षक नौकरियों के वायदों के साथ भारत और अफगानिस्तान में बेईमान एजेंटों द्वारा उनको ठगा गया था। 30 दिन के टूरिस्ट वीजा के साथ एजेंटों द्वारा अफगानिस्तान में उनके आगमन की व्यवस्था की जाती है तथा वे उस समय फंस जाते हैं उनको वीजा की अवधि के अंदर काम नहीं मिलता है, अधिकांश मामलों में संबंधित एजेंटों द्वारा उनके पासपोर्ट नहीं लौटाए जाते हैं, जबकि कुछ का पैसा भी खत्म हो जाता है। इन सभी मामलों में मिशन ने पासपोर्ट के गुम होने की स्थिति में ई सी के निर्गम, अफगान प्राधिकारियों द्वारा वीजा से अधिक अवधि तक प्रवास के लिए दंड में छूट तथा कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के दौरान आवास की सुविधा प्रदान करने के बाद उनकी वापसी की व्यवस्था करने के लिए अटार्नी जनरल का कार्यालय तथा एयरपोर्ट प्राधिकारियों सहित अफगान प्राधिकारियों से संपर्क स्थापित किया। वर्ष 2015 के दौरान आई सी डब्ल्यू एफ से मिशन द्वारा 32 विपदाग्रस्त भारतीयों के लिए रिटर्न एयर टिकट की भी व्यवस्था की गई, जबकि 26 विपदाग्रस्त भारतीयों के लिए भारत में उनके परिवार के सदस्यों के माध्यम से रिटर्न एयर टिकट की व्यवस्था की गई। भारत और अफगानिस्तान में इस काम में शामिल एजेंटों के ब्यौरों को

उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एम ओ आई ए तथा अफगान प्राधिकारियों के साथ साझा किया गया।

अफगानिस्तान में भारतीय डायसपोरा का प्राथमिक सरोकार सुरक्षा है। वर्ष 2014 के दौरान काबुल में विभिन्न आतंकी हमलों में 4 भारतीय मारे गए, दो 22 जुलाई को कैंप गिब्सन में जहां वे डिंकार्प्स के लिए काम कर रहे थे तथा दो 8 दिसंबर को बगराम एयरबेस में। होटल पार्क पैलेस, काबुल में हमले में 13 मई 2015 को चार भारतीय मारे गए। मिशन ने उनके नश्वर अवशेषों को शीघ्रता से भेजने के लिए संपर्क स्थापित किया तथा सहायता प्रदान की और उनके परिवारों को सूचित किया। मिशन सभी पंजीकृत भारतीयों को ईमेल एवं वाट्सऐप के माध्यम से समय समय पर सुरक्षा परामर्शी जारी करता है तथा सुरक्षा की स्थिति के बारे में उनको जानकारी प्रदान करता है और अफगानिस्तान में रहते समय बरते जाने वाले सुरक्षा के एहतियातों के बारे में अवगत कराता है। हेरात से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर जिंदाजन जिले में सहादत कस्बे से 2 जून 2014 को सशस्त्र उग्रवादियों द्वारा एलेक्सिस प्रेम कुमार, जो जेस्यूट रिफ्यूजी सर्विस (जे आर एस) नामक एक एन जी ओ के लिए काम करता था, नामक एक भारतीय का अपहरण कर लिया गया। मिशन तथा भारत सरकार, नई दिल्ली के अधिकारियों के प्रयासों से उसे उड़ाया गया तथा 22 फरवरी 2015 को भारत वापस भेजा गया। गजेन्द्र सिंह नामक एक अन्य भारतीय, जो अपने अफगानी बहनोई के निमंत्रण पर काबुल घूमने आया था, जलालाबाद से गायब हो गया, जहां वह अपने बहनोई तथा कुछ अन्य अफगानियों के साथ 1 जून 2014 को गया था। अफगान प्राधिकारियों से मिशन द्वारा उसकी सुरक्षित बरामदगी के लिए बार बार अनुरोध किया गया है परंतु अभी तक उसका पता नहीं चला है। तथापि इस मामले में शामिल पांच अफगानी नागरिकों में से दो को 8 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया है, जबकि तीन अभी भी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं।

उपयोगी संसाधन :

भारतीय दूतावास, काबुल की वेबसाइट :
http://eoi.gov.in/kabul/
भारतीय दूतावास, काबुल का ट्वीटर :
https://twitter.com/indianembkabul
भारतीय दूतावास, काबुल का फेसबुक :
https://www.facebook.com/IndiaInAfghanistan

***

फरवरी 2016